

किसान आंदोलन 2.0 और MSP

प्रलिस के लयि:

[न्यूनतम समर्थन मूल्य](#), कसिन आंदोलन 2.0 और MSP, [भूमि अधगिरहण अधनियम, 2013](#), [वदियुत \(संशोधन\) वधियक 2020](#), डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन आयोग की रपौरट ।

मेन्स के लयि:

कसिन आंदोलन 2.0 और MSP, भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों का संग्रहण, वकिस, वकिस और रोजगार से संबंधति मुददे ।

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यौं?

[न्यूनतम समर्थन मूल्य \(Minimum Support Price - MSP\)](#) के लयि कानूनी गारंटी की मांग को लेकर पंजाब, हरयिणा और उत्तर प्रदेश के कसिन 'दलिली चलो' वरिोध प्रदर्शन में दलिली की ओर मारुच कर रहे हैं ।

- वर्ष 2020 में कसिनौं ने, दलिली की सीमाओं पर, सरकार द्वारा पारति तीन [कृषि कानूनों का वरिोध](#) कयि, जसिके कारण वर्ष 2021 में उन्हें नरिसुत कर दयि गय।
- ये कानून थे- [कृषि उपज वाणजिय एवं व्यापार \(संवरद्धन एवं सुवधि\) वधियक, 2020](#), [मूल्य आशवासन पर कसिन \(बंदोबसती और सुरकषा\) समझौता और कृषि सेवा वधियक, 2020](#), [आवश्यक वस्तु \(संशोधन\) वधियक, 2020](#)

कसिनौं की मुख्य मांगें क्यौं हैं?

- कसिनौं के 12 सूत्रीय एजेंडे में मुख्य मांग सभी फसलों के लयि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी के लयि एक कानून और डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन (मनकोमबु संबाशविन स्वामीनाथन) आयोग की रपौरट के अनुसार फसल की कीमतों का नरिधारण करना है ।
 - स्वामीनाथन आयोग की रपौरट में कहा गय है कसरकार को **MSP को उत्पादन की भारत औसत लागत से कम-से-कम 50% अधिक बढ़ाना चाहयि** । इसे **C2+ 50% फॉर्मूला** के रूप में भी जाना जत है ।
 - इसमें कसिनौं को 50% रटिरन देने के लयि **पूंजी की अनुमानति लागत** और भूमिपर करिय (जसि 'सी2' कहा जत है) शामिल है ।
 - भूमि, श्रम और पूंजी जैसे संसाधनों के उपयोग की अवसर लागत को ध्यान में रखने के लयि **अध्यारोपति लागत (imputed cost)** का उपयोग कयि जत है ।
 - **पूंजी की अध्यारोपति लागत** उस ब्याज या रटिरन को दर्शाती है जो अरुजति कयि जा सकत थ। यद कृषि में नविश की गई पूंजी को कहीं और नविश कयि जत ।
- अन्य मांगें:
 - कसिनौं और मजदूरों की पूरण करुज माफी;
 - [भूमि अधगिरहण अधनियम, 2013](#) का कार्यानवन, जसिमें अधगिरहण से पहले कसिनौं से लखिति सहमति और कलेक्टर दर से चार गुना मुआवज़ा देने का प्रावधान है ।
 - **संग्राहक दर (collector rate)** वह न्यूनतम मूल्य है जसि पर कसिी संपत्तिको खरीदते थ। बेचते समय पंजीकृत कयि जा सकत है । **वे संपत्तियों के कम मूल्यांकन और कर चोरी को रोकने के लयि** एक संदर्भ बडु के रूप में कार्य करते हैं ।
 - अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी हत्याकांड के अपराधियों को सज़ा;
 - भारत को [वशिव व्यापार संगठन \(World Trade Organization - WTO\)](#) से बाहर हो जाना चाहयि और सभी [मुक्त व्यापार समझौतों \(free trade agreements - FTAs\)](#) पर रोक लगा देनी चाहयि ।
 - कसिनौं और खेतहिर मजदूरों के लयि पेंशन ।
 - वर्ष 2020 में दलिली वरिोध प्रदर्शन के दौरान मरने वाले कसिनौं के लयि मुआवज़ा, जसिमें परिवार के एक सदस्य के लयि नौकरी भी शामिल है ।

WTO और FTA से संबंधित किसानों की चर्चाएँ क्या हैं?

- बाज़ार तक पहुँच:
 - किसानों को चर्चा है कि FTA और WTO नियमों से सस्ते कृषिआयात से प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, जिससे घरेलू कीमतें कम हो सकती हैं तथा स्थानीय उत्पादकों को नुकसान हो सकता है।
 - किसान इन समझौतों को छोटे और मध्यम आकार के किसानों के बजाय बहुराष्ट्रीय नगियों तथा बड़े पैमाने के कृषिव्यवसायों के पक्ष में मानते हैं।
- आयात वस्तुएँ:
 - इन समझौतों से अन्य देशों से सब्सिडी वाले कृषिउत्पादों की आमद होती है, जिससे घरेलू बाज़ार में बाढ़ आ सकती है और स्थानीय रूप से उत्पादित फसलों की कीमतें कम हो सकती हैं।
 - इससे भारतीय किसानों के लिये प्रतिस्पर्धा करना और अपनी आजीविका बनाए रखना मुश्किल हो सकता है।
- कृषिपद्धतियों पर प्रभाव:
 - अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते कृषिपद्धतियों पर ऐसे नियम या मानक भी लागू करते हैं जिनमें भारतीय किसान अपनी पारंपरिक खेती पद्धतियों के साथ बोज़लि या असंगत पाते हैं।
 - इसमें कीटनाशकों के उपयोग, [आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव](#) या पर्यावरण मानकों से संबंधित आवश्यकताएँ शामिल हो सकती हैं।
- संप्रभुता और स्वायत्तता:
 - कुछ किसान WTO से हटने तथा मुक्त व्यापार समझौतों पर अंकुश लगाने को भारत की कृषिनीतियों पर संपूर्ण प्रभुत्व और नियंत्रण हासिल करने के एक तरीके के रूप में देखते हैं।
 - उनका तर्क है कि ऐसे समझौते लघु पैमाने के किसानों के हितों को प्राथमिकता देने वाली नीतियों के कार्यान्वयन और नागरिकों के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार की क्षमता को सीमित करते हैं।

MSP और किसानों की मांग की वर्तमान स्थिति क्या है?

- मौजूदा MSP बनाम कृषकों की मांगे:
 - रबी मार्केटिंग सीज़न 2024-25 के लिये सरकार द्वारा निर्धारित गेहूँ का MSP 2,275 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है जो किसानों द्वारा मांगी गई लागत यानी C2 प्लस 50% से अधिक है।
 - हालाँकि MSP A2+FL फॉर्मूला पर आधारित है जिसमें केवल किसानों द्वारा भुगतान की गई लागत शामिल है जिसके परिणामस्वरूप C2 प्लस 50% की तुलना में MSP कम है।
- CACP की अनुशंसाएँ और कार्यप्रणाली:
 - कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) A2+FL फॉर्मूले के आधार पर MSP निर्धारित करने की अनुशंसा करता है जिसमें केवल भुगतान की गई लागत तथा पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य शामिल होता है।
 - यह C2 फॉर्मूले से भिन्न है जिसमें किसान के स्वामित्व वाली भूमि के करिये और स्थिर पूँजी पर ब्याज़ जैसे अतिरिक्त कारक शामिल हैं।
- उत्पादन लागत पर रटिर्न:
 - पंजाब में गेहूँ का उत्पादन लागत (C2) 1,503 रुपए प्रति क्विंटल है जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,275 रुपए प्रति क्विंटल है।
 - इसका अर्थ यह है कि किसानों को उत्पादन लागत से 772 रुपए प्रति क्विंटल अधिक मिलाता है जो उत्पादन लागत पर 51.36% का रटिर्न दर्शाता है।
 - इसी प्रकार पंजाब में धान की उत्पादन लागत पर रटिर्न 49% का था और A2+FL पर यह 152% था।

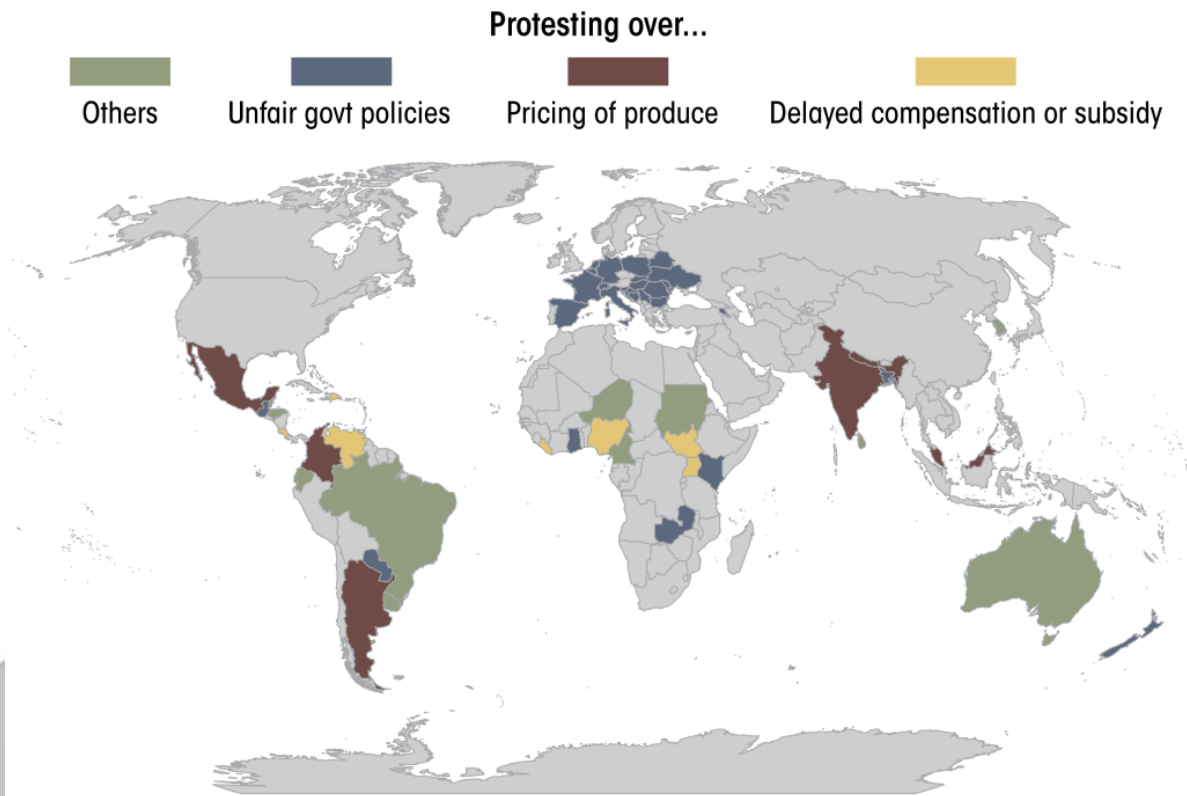
वर्ष भर में किसान वरिध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं?

- दक्षिण अमेरिका:
 - किसान नरियात के लिये प्रतिक्विल वनिमिय दर, अधिपति उच्च कर, आर्थिक मंदी और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं जैसे कारकों के कारण वरिध कर रहे हैं जिनसे फसलें प्रभावित होती हैं तथा कृषिउत्पादन कम होता है।
 - ब्राज़ील में कृषक वर्ग आनुवंशिक रूप से संशोधित मक्का के परिणामस्वरूप होने वाली अनुचित प्रतिस्पर्धा के वरिध वरिध प्रदर्शन कर रहे हैं।
 - वेनेज़ुएला में किसान सहायिकी युक्त डीज़ल की मांग कर रहे हैं।
 - कोलंबियाई धान उत्पादक अपनी फसल के लिये कीमतों में वृद्धि करने की मांग कर रहे हैं।
- यूरोप:
 - किसान फसल की कम कीमतों, बढ़ती लागत, अल्प लागत वाले आयात और [यूरोपीय संघ](#) द्वारा अधिपति सख्त पर्यावरण नियमों का वरिध कर रहे हैं।
 - फ्रांस में अल्प लागत वाले आयात, अपर्याप्त सहायिकी और उच्च उत्पादन लागत के वरिध वरिध प्रदर्शन किये जा रहे हैं।
- उत्तर और मध्य अमेरिका:
 - मैक्सिकन किसान मक्के और गेहूँ की फसल के लिये दिये जाने वाले अनुचित कीमतों का वरिध कर रहे हैं जबकि कोस्टा रिका के किसान कर्ज़ के बोझ से छुटकारा पाने के लिये अधिक सरकारी सहायता की मांग कर रहे हैं।
 - मेक्सिको के चड्डिआहुआ प्रांत में संयुक्त राज्य अमेरिका को सीमित जल आपूर्ति नरियात करने की योजना पर वरिध प्रदर्शन हुआ।
- एशिया:
 - भारतीय किसान फसल की गारंटीकृत कीमतों, आय दोगुनी करने और ऋण माफी की मांग को लेकर वरिध प्रदर्शन कर रहे हैं।

- नेपाल में आयातति भारतीय सब्जियों की अनुचित कीमतों के कारण वरीध प्रदर्शन कया जा रहा है ।
- मलेशियाई और नेपाली कसिन क्रमशः चावल तथा गन्ने की कम कीमतों का वरीध कर रहे हैं ।
- **ओशनिया:**
 - न्यूज़ीलैंड के कसिन खाद्य उत्पादकों को प्रभावति करने वाले सरकारी नयिमों का वरीध करते हैं जबकि ऑस्ट्रेलियाई कसिन अपनी कृषि भूमि से गुज़रने वाली हाई-वोल्टेज वदियुत लाइनों का वरीध कर रहे हैं ।

FARM PROTESTS GLOBALLY

Since 2023, at least 65 countries have reported protests organised by agricultural workers with reasons ranging from minimum support price like in India, to unfair governmental policies — like in Europe — to outright displacement or eviction of farmers as seen in Benin or Sudan in Africa



Source: Media reports

Down To Earth

न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है?

- **परचिय:**
 - MSP वह गारंटीकृत राशति है जो कसिनों को तब दी जाती है जब सरकार उनकी फसल खरीदती है ।
 - MSP [कृषि लागत और मूल्य आयोग \(Commission for Agricultural Costs and Prices- CACP\)](#) की सफिराशियों पर आधारति है, जो उत्पादन लागत, मांग तथा आपूर्ति, बाज़ार मूल्य रुझान, अंतर-फसल मूल्य समानता आदि जैसे वभिन्नि कारकों पर वचिर करता है ।
 - CACP कृषि एवं कसिन कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है । इसका गठन जनवरी 1965 में कया गया ।
 - भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में [आर्थिक मामलों की कंबनित समिति \(CCEA\)](#) MSP के स्तर पर अंतमि नरिणय (अनुमोदन) लेती है ।
 - MSP का उद्देश्य उत्पादकों को उनकी फसल के लयि लाभकारी मूल्य सुनिश्चिति करना और [फसल वविधीकरण](#) को प्रोत्साहति करना है ।
- **MSP के तहत फसलें:**
 - CACP, [22 अधविषित फसलें \(Mandated Crops\)](#) के लयि MSP और गन्ने के लयि [उचिति तथा लाभकारी मूल्य \(FRP\)](#) की सफिराशि करता है ।

◦ अधदिष्ट फसलों में खरीफ सीज़न की 14 फसलें, **6 रबी फसलें** और 2 अन्य वाणज्यिक फसलें शामिल हैं।

■ **उत्पादन लागत के तीन प्रकार:**

- CACP प्रत्येक फसल के लिये राज्य और अखलि भारतीय औसत स्तर पर **तीन प्रकार की उत्पादन लागत** का अनुमान लगाता है।
 - **'A2'**: इसके तहत **किसान द्वारा** बीज, उर्वरकों, कीटनाशकों, श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, संचाई आदि पर किये गए **प्रत्यक्ष व्यय** को शामिल किया जाता है।
 - **A2+FL'**: इसके तहत **'A2' के साथ-साथ अवैतनिक पारिवारिक श्रम** का एक अधरिपति मूल्य शामिल किया जाता है।
 - **'C2'**: यह एक अधिक व्यापक लागत है, क्योंकि इसके अंतर्गत 'A2+FL' में किसान की स्वामित्व वाली भूमि और स्थरि संपत्ति के करिए तथा ब्याज को भी शामिल किया जाता है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की सफिरशि करते समय **CACP** द्वारा **'A2+FL' और 'C2' दोनों** लागतों पर वचिर किया जाता है।
 - CACP द्वारा 'A2+FL' लागत की ही गणना प्रतफिल के लिये की जाती है।
 - जबकि 'C2' लागत का उपयोग CACP द्वारा मुख्य रूप से बेंचमार्क लागत के रूप में किया जाता है, यह देखने के लिये किक्या उनके द्वारा अनुशंसति MSP कम-से-कम कुछ प्रमुख उत्पादक राज्यों में इन लागतों को कवर करते हैं।

■ **MSP की आवश्यकता:**

- वर्ष 2014 और वर्ष 2015 में लगातार दो सूखे (Droughts) कघटनाओं के कारण किसानों को वर्ष 2014 के बाद से वसतु की कीमतों में लगातार गशिवट का सामना करना पड़ा।
- **वमिद्रीकरण (Demonetisation) एवं 'वसतु एवं सेवा कर'** ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था, मुख्य रूप से गैर-कृषि क्षेत्र के साथ-साथ कृषि क्षेत्र को भी नकारात्मक रूप से प्रभावति किया है।
- वर्ष 2016-17 के बाद अर्थव्यवस्था में जारी मंदी और उसके बाद कोवडि महामारी के कारण अधकिंश किसानों के लिये परदृश्य वकिट बना हुआ है।
- डीज़ल, बजिली एवं उर्वरकों के लिये उच्च इनपुट कीमतों ने उनके संकट को और बढ़ाया है।
- यह सुनश्चित करता है कि किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिले, जिससे कृषि संकट एवं नरिधनता को कम करने में मदद मिलति है। यह उन राज्यों में वशेष रूप से प्रमुख है जहाँ कृषि आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है।



₹ न्यूनतम समर्थन मूल्य Minimum Support Price (MSP)

वह दर जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है; किसानों द्वारा वहाँ किये गए उत्पादन लागत के कम-से-कम 1.5 गुणा की गणना के आधार पर

❖ सिफारिश:

❖ 'कृषि लागत और मूल्य आयोग' (CACP) द्वारा सरकार को 22 अधिदिष्ट फसलों के लिये 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) तथा गन्ने के लिये 'उचित और लाभकारी मूल्य' (FRP) की सिफारिश की जाती है।

❖ 22 अधिदिष्ट फसलें :

(14 खरीफ, 6 रबी और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें)

- ❖ 7 अनाज- धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी
- ❖ 5 दालें- चना, अरहर/तूर, मूंग, उड़द और मसूर
- ❖ 7 तिलहन- मूंगफली, सफेद सरसों/सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुंभ और रामतिल
- ❖ कच्चा कपास
- ❖ कच्चा जूट
- ❖ नारियल/गरी (कोपरा)

MSP वह मूल्य है जिस पर सरकार को किसानों से अधिदिष्ट फसलों की खरीद करनी होती है, यदि बाजार मूल्य इससे कम हो जाता है

❖ MSP की सिफारिश में प्रयुक्त कारक:

- ❖ फसल की खेती में आने वाली लागत
- ❖ फसल के लिये आपूर्ति एवं मांग की स्थिति
- ❖ बाजार मूल्य प्रवृत्तियाँ
- ❖ अंतर-फसल मूल्य समता
- ❖ उपभोक्ताओं के लिये निहितार्थ (मुद्रास्फीति)
- ❖ पर्यावरण (मिट्टी तथा पानी के उपयोग)
- ❖ कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें
- ❖ MSP की सिफारिश करते समय CACP द्वारा 'A2+FL' और 'C2' दोनों लागतों पर विचार किया जाता है।
- ❖ MSP का कोई वैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं है - कोई भी किसान अधिकार के रूप में MSP की मांग नहीं कर सकता है

भारत में MSP व्यवस्था से संबद्ध समस्याएँ:

■ सीमतिता:

- 23 फसलों के लिये MSP की आधिकारिक घोषणा के वपिरीत केवल दो- चावल और गेहूँ की खरीद की जाती है क्योंकि इनहीं दोनों खाद्यान्नों का वतिरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत किया जाता है। शेष अन्य फसलों के लिये यह अधिकांशतः तदर्थ व महत्त्वहीन ही है।
- शेष अन्य फसलों के लिये यह अधिकांशतः तदर्थ व महत्त्वहीन है। इसका अर्थ यह है कि गैर-लक्षित फसलें उगाने वाले अधिकांश किसानों को MSP से लाभ नहीं मलित है।

■ अप्रभावी कार्यान्वयन:

- वर्ष 2015 की शांता कुमार समिति की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को MSP का मात्र 6% ही प्राप्त हुआ।
- जिसका अर्थ यह है कि देश के 94% किसान MSP के लाभ से वंचित रहे। इसका मुख्य कारण किसानों के लिये अपर्याप्त खरीद तंत्र और बाज़ार पहुँच है।

■ प्रवण फसल का प्रभुत्व:

- चावल और गेहूँ के लिये MSP पर ध्यान केंद्रित करने से इन दो प्रमुख खाद्य पदार्थों के पक्ष में फसल पैटर्न में बदलाव आया है। इन फसलों पर अत्यधिक बल देने से पारस्थितिक, आर्थिक और पोषण संबंधी प्रभाव पड़ सकते हैं।
- यह बाज़ार की मांगों के अनुरूप नहीं हो सकता है, जिससे किसानों के लिये आय की संभावना सीमति हो सकती है।

■ बचौलियों पर नरिभरता:

- MSP-आधारित खरीद प्रणाली में प्रायः बचौलिय, कमीशन एजेंट और कृषि उपज बाज़ार समितियों (APMC) के अधिकारी जैसे बचौलिय शामिल होते हैं।
- विशेष रूप से छोटे किसानों के लिये इन चैनलों तक पहुँच चुनौतीपूर्ण हो सकती है, जिससे अक्षमताएँ उत्पन्न होंगी और उनके लिये लाभ कम हो जाएगा।

■ सरकार पर बोझ:

- सरकार MSP समर्थित फसलों के बफर स्टॉक की खरीद और रखरखाव में एक वृहत वतितीय बोझ उठाती है। इससे उन संसाधनों का वचिलन हो जाता है जनिहें अन्य कृषि या ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिये आवंटित किया जा सकता है।

आगे की राह

- फसल वविधीकरण को प्रोत्साहित करने और चावल व गेहूँ के प्रभुत्व को कम करने के लिये सरकार धीरे-धीरे MSP समर्थन हेतु पात्र फसलों की सूची का वसितार कर सकती है। इससे किसानों को अधिक विकल्प मल्लिगे और बाज़ार की मांग के अनुरूप फसलों की खेती को बढ़ावा मल्लिगा।
- MSP मुद्दे का समाधान करने के लिये एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें किसानों के हतियों और व्यापक आर्थिक नहितार्थ कोई शामिल किया जाना चाहिये।
 - MSP परकिलन पद्धतपर पुनः वचिार करने और MSP नरिधारित करने के लिये एक नषिपक्ष तथा पारदर्शी प्रक्रिया सुनश्चिति करने से किसानों द्वारा उठाई गई कुछ चतिताओं को दूर करने में मदद मल्लि सकती है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. नमिनलखित कथनों पर वचिार कीजयि: (2020)

1. सभी अनाजों, दालों एवं तलिनहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर प्रापण भारत के किसी भी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश (यू.टी.) में असीमति होता है।
2. अनाजों एवं दालों का MSP किसी भी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में उस स्तर पर नरिधारित किया जाता है, जिस स्तर पर बाज़ार मूल्य कभी नहीं पहुँच पाते।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: d

प्रश्न. नमिनलखित कथनों पर वचिार कीजयि: (2023)

1. भारत सरकार काले तलि नाइजर (गुइज़ोटिया एबसिनिका) के बीजों के लिये न्यूनतम समर्थन कीमत उपलब्ध कराती है।
2. काले तलि की खेती खरीफ की फसल के रूप में की जाती है।
3. भारत के कुछ जनजातीय लोग काले तलि के बीजों का तेल भोजन पकाने के लिये प्रयोग में लाते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई भी नहीं

उत्तर: (c)

??????:

प्रश्न. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) से आप क्या समझते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषकों का नमिन आय फंदे से किस प्रकार बचाव करेगा? (2018)

प्रश्न. सहायकियों सस्यन प्रतरूप, सस्य वविधिता और कृषकों की आर्थिक स्थिति किस प्रकार प्रभावति करती है? लघु और सीमांत कृषकों के लिये फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा खाद्य प्रसंस्करण का क्या महत्त्व है? (2017)

प्रश्न. धान-गेहूँ प्रणाली को सफल बनाने के लिये कौन-से प्रमुख कारक उत्तरदायी हैं? इस सफलता के बावजूद यह प्रणाली भारत में अभिशाप कैसे बन गई है? (2020)

प्रश्न. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) के द्वारा कीमत सहायिकी का प्रतस्थापन भारत में सहायकियों के परदृश्य का किस प्रकार परिवर्तन कर सकता है? चर्चा कीजिये। (2015)

प्रश्न. विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ) एक महत्त्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्था है जहाँ लिये गए नरिणय देशों को गहराई से प्रभावति करते हैं। डब्ल्यू.टी.ओ का क्या अधदिश (मैडेट) है और उसके नरिणय किस प्रकार बंधनकारी हैं? खाद्य सुरक्षा पर वचिर-वमिर्श के पछिले चक्र पर भारत के दृढ-मत का समालोचनात्मक वशिलेषण कीजिये। (2014)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/farmers-protest-2-0-and-msp>